

न्यायालय अतिरिक्त जिला कलक्टर, बूंदी

AK

निवासीन अधिकारी-

अमानुल्लाह खान,
आर.ए.एस.

मिसल संख्या
14 / अपील / 20

तारीख दायरा
30.06.2020

तारीख फैसला
17.09.2021

1. कालू उर्फ चौथमल पुत्र लाडू जाति भील निवासी मराड़ी तहसील हिण्डोली जिला बून्दी हाल निवासी मुण्डिया कलां तहसील टोड़ारायसिंह जिला टोंक राज.।
2. किश्मत पुत्री लाडू जाति भील निवासी मराड़ी तहसील हिण्डोली जिला बून्दी हाल निवासी मुण्डिया कलां तहसील टोड़ारायसिंह जिला टोंक राज.।
3. आशा पुत्री लाडू जाति भील निवासी मराड़ी तहसील हिण्डोली जिला बून्दी हाल निवासी मुण्डिया कलां तहसील टोड़ारायसिंह जिला टोंक राज.।

-अपीलान्त

बनाम

1. महावीर पुत्र लाडू जाति भील निवासी मराड़ी हाल निवासी जड़ का नया गावं द्वारा पोषी मीणा निवासी जड़ का नया गावं तहसील हिण्डोली जिला बून्दी राज.।
2. राजू पुत्र लाडू जाति भील निवासी ग्राम मराड़ी तहसील हिण्डोली जिला बून्दी राज.।
3. रामा पुत्र रतन जाति भील निवासी ग्राम मराड़ी तहसील हिण्डोली जिला बून्दी राज.।
4. राज. राज्य सरकार द्वारा श्रीमान् तहसीलदार साहब हिण्डोली जिला बून्दी राज.।

-रेस्पोडेन्ड

उपरिथत-

अपीलान्त संख्या 1 लगायत 3 की ओर से - श्री शम्भूदयाल शर्मा एड०
रेस्पो० संख्या 1 लगायत 3 के विरुद्ध एकपक्षीय कार्यवाही
रेस्पो० संख्या 4 की ओर से - परोकार सरकार

निर्णय

यह अपील तहसीलदार हिण्डोली द्वारा तस्दीकशुद्धा नामान्तरकरण संख्या 251 दिनांक 24.06.2004 से अप्रसन्न होकर अन्तर्गत धारा 75 भू-राजस्व अधिनियम, 1956 इस न्यायालय में पेश की गई है। अपीलाधीन नामान्तरकरण से कृषि भूमि खसरा संख्या 14 रकबा 2 बीघा 5 बीस्वा, 15 रकबा 2 बीघा 12 बीस्वा, 16 रकबा 4 बीघा 5 बीस्वा, 17 रकबा 7 बीघा 6 बीस्वा वाके ग्राम मराड़ी मृतक खातेदार लाडू के स्थान पर रेस्पोडेन्ड

ख्या 1 महावीर व रेस्पोजेन्ड संख्या 2 राजू का नाम दर्ज किया गया है। अपील प्रस्तुत होने पर दर्ज रजिस्टर कर रेस्पोजेन्ड तथा अधीनस्थ न्यायालय का रेकार्ड तलब किया गया। रेस्पोजेन्ड संख्या 1 लगायत 3 बावजूद सूचना के न्यायालय में उपस्थित नहीं होने से उनके विरुद्ध एकपक्षीय कार्यवाही अमल में लाई गई।

बहस उभयपक्ष समाप्त की गई।

अभिभाषक अपीलांत ने बहस के दौरान तर्क प्रस्तुत किये कि विवादित कृषि भूमि खसरा संख्या 14 रकबा 2 बीघा 5 बीस्वा, 15 रकबा 2 बीघा 12 बीस्वा, 16 रकबा 4 बीघा 5 बीस्वा, 17 रकबा 7 बीघा 6 बीस्वा वाके ग्राम मराड़ी में विस्थित हैं जिसके खातेदार रामा, लाडू पि० रतना कौम भील थे। सहखातेदार लाडू की मृत्यु के पश्चात फौती नामान्तरकरण दर्ज किया गया है जिसमें रेस्पोजेन्ड संख्या 1 व 2 का नाम दर्ज किया है जबकि मृतक लाडू के वारिसान अपीलांत संख्या 1 लगायत 3 भी हैं। मृतक लाडू के वारिसान की मजमें आम में कोई जानकारी नहीं की गई है। लाडू की मृत्यु के उपरान्त नटीबाई जो लाडू की पत्नि थी वह अपीलांत को अपने साथ लेकर ग्राम मुण्डियां कला जिला टोंक चली गई थी। लाडू की मृत्यु के समय रेस्पोजेन्ड राजू व महावीर बड़े होने के कारण मराड़ी में ही अपने बड़े पिता रामा रेस्पोजेन्ड संख्या 3 के पास रह गये। तहसीलदार हिण्डोली द्वारा मृतक लाडू के विधिक वारिसान बाबत् कोई जांच नहीं की गई है, न ही अपीलांतस को सुनवाई का अवसर प्रदान किया गया है। अपीलांतस के पिता मृतक लाडू की भूमि अपने बाड़े भाई रामा के पास रहन रखी हुई थी। अपीलांत दिनांक 15.05.2020 को ग्राम मराड़ी आया और आपसी सहमति से रूपयों का भुगतान रामा को किया। तत्पश्चात पटवारी हल्का से नकल प्राप्त करने के दौरान यह तथ्य सामने आये कि मृतक लाडू के स्थान पर केवल रेस्पोजेन्ड संख्या 1 व 2 का नाम दर्ज किया गया है। नामान्तरकरण की प्रथम जानकारी दिनांक 18.05.2020 को नकल प्राप्त करने पर हुई। नकल प्राप्त होने पर ज्ञान की तिथि से अपील अंतर्गत अवधि मध्य प्रस्तुत है यदि अपील को पेश करने में विलम्ब माना जाता है तो अपील के साथ धारा 5 भारतीय मियाद अधिनियम के तहत प्रार्थना पत्र अपील के साथ पृथक से प्रस्तुत है। विलम्ब को क्षम्य किया जावे। अतः अपील अपीलांत स्वीकार की जाकर तहसीलदार हिण्डोली द्वारा पारित आदेश दिनांक 24.06.2004 खारिज किया जावे।

वकील रेस्पोजेन्ड संख्या 4 की ओर से राजकीय अभिभाषक ने व्यक्त किया कि प्रकरण का निस्तारण गुणावगुण पर किया जाना उचित होगा।

हमने पत्रावली का आद्योपान्त अवलोकन कर बहस उभयपक्ष पर मनन किया गया। हस्तगत प्रकरण में यह तथ्य प्रकट है कि अपीलाधीन नामान्तरकरण दिनांक 24.06.2004 से मृतक लाडू के स्थान पर रेस्पोजेन्ड संख्या 1 महावीर व रेस्पोजेन्ड संख्या 2 राजू का नाम अंकित किया गया है। अपीलांतस का मुख्य तर्क यह है कि वह भी मृतक लाडू के विधिक वारिसान हैं और विवादित नामान्तरकरण तस्दीक करते समय अधीनस्थ न्यायालय ने वारिसान बाबत् कोई जांच नहीं की गई है न ही सुनवाई का समुचित अवसर प्रदान किया गया है। उक्त तर्क से हम पूर्णतया सहमत हैं। न्याय का नैसर्गिक सिद्धांत यह है कि पक्षकारान को सुनवाई हेतु समुचित अवसर प्रदान किया जाना चाहिए। हस्तगत प्रकरण में पक्षकारान को सुनवाई का समुचित अवसर प्रदान नहीं किया गया है।

अतएव: परिणामस्वरूप अपील सारवान पाए जाने से स्वीकार की जाकर अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित आदेश दिनांक 24.06.2004 को निरस्त किया जाता है साथ ही

को इस निर्देश के साथ अधीनस्थ न्यायालय को प्रतिप्रेषित किया जाता है कि वह लाडू के सभी विधिक वारिसान को समुचित सुनवाई एवं साक्ष्य प्रस्तुत करने का अवसर प्रदान करते हुये संपूर्ण विधिक जांच कर नये सिरे से अपना निर्णय पारित करे। पत्रावली फ़ैसलें में शुमार होकर बाद तकमील दाखिल दफ़्तर हो। अधीनस्थ न्यायालय की पत्रावली मय निर्णय प्रति के भिजवाये जावें।

निर्णय आज दिनांक 17.09.2021 को खुले न्यायालय में सुनाया गया।

अति० ज़िला कलक्टर

बूंदी (राज०)

(अमानुल्लाह खान)

अति० ज़िला कलक्टर,

बूंदी